भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1364
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

नौकरियाँ छूट जाना

1364. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार, मई से जून, 2022 तक 1.4 करोड़ भारतीयों ने अपनी नौकरियाँ गंवा दी हैं;

(ख) क्या जून 2022 में रोजगार पिछले 12 महीनों में सबसे कम रहा है;

(ग) क्या जून 2022 में वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच 2.5 मिलियन नौकरियों की कमी हुई है;

(घ) क्या बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु 'मेक इन इंडिया' योजना पर्याप्त रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो 'मेक इन इंडिया' योजना की शुरुआत से अब तक सृजित रोजगार का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) एवं कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान निम्नानुसार हैः

वर्ष	बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)
2018-19	5.8	47.3
2019-20	4.8	50.9
2020-21	4.2	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़ें, बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिससे पता चलता है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आंकड़े, औपचारिक क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कामगार को कवर करता है। ईपीएफओ अंशदाताओं में शुद्ध वृद्धि, रोजगार सृजन/औपचारिक रोजगार बाजार की सीमा और संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। ईपीएफ अंशदाताओं में अप्रैल 2022 में 15.4 लाख की तुलना में मई 2022 के दौरान इसमें शुद्ध वृद्धि 16.8 लाख हो गई थी।

(घ) और (ङ): 'मेक इन इंडिया' पहल, 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, श्रेणी के बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया में बढ़ावा दिया है। 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कोविड से संबंधित व्यवधानों के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के सकारात्मक समग्र विकास की प्रवृत्ति रही है। इस क्षेत्र में कुल रोजगार वर्ष 2017-18 में 5.7 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.24 करोड़ हो गया है।

*****